पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

द्वितीय पेंशन सम्मेलन

सार्वभौमिक पेंशन - विस्तार, पर्याप्तता और निरंतरता

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा " सार्वभौमिक पेंशन - विस्तार, पर्याप्तता और निरंतरता" विषय के अंतर्गत 4 फरवरी 2016 को द्वितीय पेंशन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य पेंशन सेक्टर से सम्बद्ध चुनौतियों और देशभर में पेंशन सेक्टर के विस्तार की आवश्यकता और तरीकों पर विचार-विमर्श, विवेचन और बहस के लिए एक मंच प्रदान करना था।

सम्मेलन के शुरूआती सत्र को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोगों को आय सुरक्षा , स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन बीमा के साथ-साथ सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया और भारतीय नगारिकों को साधनों और जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाकर उन्हें स्वयं की सेवानिवृत्ति का अधिठाष्ता बनाने के सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कौशल विकास के साथ भौगोलिक भिन्नता से युक्त युवा भारत और उभरती अर्थव्यवस्था के साथ फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही उन्होंन निचले स्तर पर वित्तीय साक्षरता को कम करने और निजी सेक्टर की प्रतिभागिता के साथ पेंशन के विस्तार की नितांत आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने देश के युवा वर्ग को जल्द से जल्द पेंशन योजनाओं में शामिल करने की महत्वता पर जोर दिया ताकि यह वर्ग वृद्धावस्था में समाज और सरकार पर निर्भर न रहे।

अपने मुख्य सम्बोेधन में पीएफआरडीए के अध्यक्ष श्री हेमंत जी. कांटेªक्टर ने पिछले दो वर्ष के दौरान एनपीएस संरचना और उत्पाद निर्माण के विकास का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 14 विनियमों का निर्माण करके पीएफआरडीए एनपीएस के सभी अंशधारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में मददगार साबित हुआ है। गत वर्ष के दौरान पीएफआरडीए ने एनपीएस के अंतर्गत पंजीकरण और अंशदान की आॅनलाइन प्रक्रिया की शुरूआत करके पेंशन उत्पादों को उपभोक्ता उपयोगी बनाने का काम किया है। वर्तमान में 16 बैंक यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 35 बैंक एसबीआई पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस सुविधा को देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाती है। निकास प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु 1 अप्रैल 2016 से आॅन लाइन निकास को अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएफआरडीए निरंतर निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम/प्रतिफल के स्वरूप में सुधार के प्रति प्रत्यनशील रहा है और इस कड़ी मे नये निवेश आरईआईटीएस, आईएनवीआईटीएस, आईडीएफ इत्यादि में निवेश को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की सुरक्षा हेतु कम जागरूकता और निम्न आय स्तर जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे असंगठित सेेक्टर के लिए और प्रयास किये जाने की जरूरत है। जनता तक एनपीएस की पहुंच के विस्तार में उचित पारितोषिक संरचना के साथ प्रभावी वितरण प्रणाली काफी सहायक सिद्ध होगी।

पेंशन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाने की जरूरत है ताकि उनकी वृद्धावस्था में उन्हें अभाव का सामना न करना पड़े।

कार्यक्रम में भारत में विश्व बैंक निदेशक श्री ओनो रुहल, वरिष्ठ पेंशन अर्थशास्त्री श्री राबर्ट पैलेसिओस, वित्तीय क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री विलियम प्राइस और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, विचारकों और प्रोफेसर मुकुल अशर, प्रो. चरन सिंह इत्यादि जैस शिक्षकों ने समूह चर्चा में हिस्सा लिया। एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न अंशधारियों जैसे - बैंक, प्वाइंट आॅफ प्रजेंस, काॅरपोरेट ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।

;पद्ध वित्तीय सेक्टर के भाग के रूप में पेंशन सुधार और वित्तीय सुधार, ;पपद्ध पेंशन सुधार के सामाजिक और आर्थिक पहलू, ;पपपद्ध भारत सरकार की समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वभौमिक पेंशन सहित पेंशन युक्त समाज की नीति और उद्देश्य को को पूरा करती पेंशन की पर्याप्तता और निरंतरता, ;पअद्ध विश्व की श्रेष्ठ पेंशन प्रणालियां, ;अद्ध पूंजी बाजार निर्भरता और आधारभूत वृद्धि हेतु दीर्घकालिक निधि के स्रोत के रूप में पेंशन निधियां ;अपद्ध पेंशन प्रणालियों से दीर्घकालिक परिणामों के लिए स्पष्ट उद्देश्य सुनिश्चित करना जेसे उप विषयों पर चर्चा की गई।

अटल पेंशन योजना में किये गये प्रदर्शन हेतु बैंकों को पुरस्कृत किया गया। भारतीय स्टेट बैंक को सर्वाधिक अटल पेंशन योजना खातों के लिए पुरस्कृत किया गया। सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आंध्रा बैंक को, निजी बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक को और काॅपरेटिव बैंक की श्रेणी में कोट्टयम जिला काॅपरेटिव बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया।

वर्तमान में, रू. 1.09 लाख करोड़ की कुल प्रबंधन के अधीन आस्ति (एयूएम) के साथ 1.14 करोड़ से अधिक अभिदाता एनपीएस में शामिल हैं।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04/02/2016